भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4170
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

केरल में डिजिटल संपर्क

4170. श्री शफी परम्बिल:
श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में मोबाइल और डिजिटल संपर्क की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत कितने गांव शामिल किए गए हैं और कितने गांव शामिल नहीं किए गए हैं;
(ख) सम्पूर्ण केरल में मोबाइल और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के संबंध में क्या चुनौतियां, यदि कोई हों, सामने आ रही हैं; और
(ग) केरल में डिजिटल असमानता को दूर करने और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) केरल के सभी 1,438 गांवों (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार) में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश में सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को

मंजूरी दी है जिसमें मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करना और लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना शामिल है।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केरल सहित देश में डिजिटल असमानता को दूर करने और डिजिटल सेवाओं के एक्सेस के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** डिजिटल साक्षरता दर में सुधार करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण भारत में भारत सरकार ने देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक स्कीम लागू की। 31 मार्च 2024 तक देश भर में 6 करोड़ के स्थान पर 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। केरल राज्य में पीएमजीदिशा स्कीम के तहत कुल 1,77,165 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया था जिनमें से कुल 1,18,132 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार से जुड़ी सेवाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमें, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्रा बुकिंग, सुविधा के लिए भुगतान शामिल हैं। जनवरी, 2025 तक केरल में 9,948 सीएससी सहित देश भर में 5.97 लाख सीएससी (ग्रामीण+शहरी) कार्यरत हैं।
- इसके अलावा केरल सहित देश भर के नागरिकों को विभिन्न पहलों जैसे न्यू एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिलॉकर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, माईस्कीम, ई-अस्पताल और माईजीओवी, आदि के तहत ई-सेवाओं का उपयोग करने में भी सक्षम बनाया गया है।

*****